[2008] 1 एस.सी.आर. 543

नगर नियोजन नगर परिषद

बनाम

राजप्पा और अन्य

(सी.ए. नं. 2836/2001)

10 जनवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और जस्टिस पी. सदाशिव, जे.जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 100:

दूसरी अपील - विधि के प्रश्न का निरूपण - आवश्यकताएँ - भूमि/संपत्ति को पैतृक संपत्ति होने का दावा करने वाला मुकदमा - विचारण न्यायालय द्वारा खारिज - प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि - उच्च न्यायालय द्वारा उलट - अपील पर, माना गया: उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके कानून का कोई प्रश्न तैयार किए बिना तथ्यों की खोज करना, ध. 100 सी.पी.सी. का उल्लंघन है - इसके अलावा, उच्च न्यायालय का निर्णय व्यावहारिक रूप से गैर-तर्कसंगत है - इसलिए, कानून का प्रश्न तैयार करने के बाद मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च

न्यायालय में भेजा जाता है - कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम धारा 284(1) - नोटिस जारी करना - अनिवार्य मांग।

प्रतिवादी नंबर 1 ने कुछ संपत्ति के संबंध में मुकदमा दायर किया और दावा किया कि यह उसकी पैतृक संपत्ति है। प्रतिवादियों ने इस आधार पर मुकदमे का विरोध किया कि मुकदमे को 1954 से टाउन नगर परिषद से संबंधित 'सेगा लोकल फंड' संपत्ति के रूप में दिखाया गया है, इसलिए उसे नगर निगम कानूनों के अनुसार निपटारे का पूरा अधिकार है। विचारण न्यायालय ने मुकदमे की भूमि/संपत्ति को 'सेगा लोकल फंड' के रूप में मानते हुए मुकदमे को प्रारंभतः खारिज कर दिया और धारा 284(1) के संदर्भ में अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। विचारण न्यायालय के फैसले को प्रथम अपीलीय अदालत ने बरकरार रखा था। अपील में, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए विचारण न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा:

1.1 उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील को कानूनी प्रश्न तैयार किए बिना अनुमति दी गई थी जो स्पष्ट रूप से धारा 100 के आदेश के विपरीत है। (पैरा - 5) [545-एफ, जी] ज्ञान दास बनाम पंचायत, ग्राम सुन्नेर कलां और अन्य जेटी (2006) 7 एससी 102; जोसेफ सेवेरेन और

अन्य बनाम बेनी मैथ्यू और अन्य। जेटी (2005) 8 एससी 509; शशिकुमार और अन्य बनाम कुन्नाथ चेल्लप्पन नायर और अन्य। जेटी (2005) 9 एससी 171; छदत सिंह बनाम बहादुर राम और अन्य। जेटी (2004) 6 एससी 296 और कन्हैयालाल बनाम अनुपकुमार जेटी (2002) 10 एससी 98 - पर भरोसा किया।

1.2 उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया। चूँकि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का निर्णय व्यावहारिक रूप से गैर-तर्कसंगत है, इसलिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि उच्च न्यायालय को ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को उलटना चाहिए। इसलिए, सीपीसी की धारा 100 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए मामले को नए सिरे से विचारण के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। (पैरा - 6) [546-ए, बी, सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2836/2001

आर.एस.ए. 1993/359 में बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश दिनांकित 12.1.1998 से।

एस. नंदा कुमार, सतीश कुमार, आनंद सेल्वम और वी.एन. रघुपति अपीलार्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस डॉ. अरिजीत पसायत ने सुनाया।

1. इस अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') की धारा 100 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर दूसरी अपील की अनुमति दी गई है। प्रतिवादी नंबर 1 ने यादगीर-बी, तालुक यादगीर में स्थित सर्वेक्षण संख्या 393/ए. ए. (पलकल) में 3 एकड़ 22 गुंटा भूमि के संबंध में एक याचिका दायर की थी। वादी ने संपत्ति को पैतृक संपत्ति होने का दावा किया।

2. प्रतिवादियों ने यह तर्क देते हुए मुकदमे का विरोध किया कि मुकदमे की भूमि को 1954 से 'सेगा लोकल फंड' संपत्ति के रूप में दिखाया जा रहा है, यह टाउन नगर परिषद, वाडगीर की संपत्ति है, इसलिए उसे नगर निगम क़ानून के अनुसार निपटने का पूरा अधिकार है, जिसे वादी वाद के माध्यम से प्रतिवादीगण को विधिपूर्ण कार्य करने से रोक नहीं सकता। आगे यह भी तर्क दिया गया कि यदि वादी के पास मुकदमे की भूमि पर बिल्कुल भी कब्जा नहीं है और उन्होंने आवासहीन व्यक्तियों को भूमि प्रदान करने के लिए नगरपालिका कानून के तहत आवश्यक अधिसूचना जारी की है और वादी ने गांव के लेखाकार को विश्वास में लेकर अपना नाम बिना किसी अधिकार के कृषक कॉलम में दर्ज करा लिया है।

इसलिए, वादी का मुकदमा बिल्कुल भी पोषणीय नहीं है। इन तर्कों के साथ, प्रतिवादियों ने मुकदमा खारिज करने की प्रार्थना की।

3. विचारण न्यायालय ने विवादकों को तैयार किया और अभिनिर्धारित किया की धारा 284(1), कर्नाटक नगर पालिकाओं अधिनियम के अनुसार, मुकदमे के लिए पूर्व नोटिस अनिवार्य है और उक्त अपेक्षा का कोई अनुपालना नहीं हुई थी और इसलिए, मुकदमा तत्काल खारिज होने योग्य था। यह भी बताया गया की खसरा पिहानी और आर.ओ.आर. में की हुई प्रविष्टि में 1954-55 से ही वाद भूमि को "सेगा लोकल फंड" के रूप में दर्शाया गया और इसे वादी या उसके पूर्वजों द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।

4. विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पाया कि वाद में कोई सार नहीं था और तदनुसार मुकदमा विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसे बरकरार रखा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने निष्कर्षों को उलट दिया और दूसरी अपील की अनुमति दी।

5. प्रारंभ में यह इंगित किया जाना चाहिए कि दूसरी अपील को कानून का प्रश्न तैयार किए बिना अनुमति दी गई थी जो स्पष्ट रूप से धारा 100 सीपीसी के विपरीत है। इस स्थिति को अनेक निर्णयों में उजागर किया गया है।. (देखें ज्ञान दास बनाम पंचायत, ग्राम सुन्नेर कलां और अन्य (जेटी 2006 (7)। एससी 102), जोसेफ सेवेरेन और अन्य बनाम

बेनी मैथ्यू और अन्य। (जेटी 2005 (8) एससी 509), शशि कुमार और अन्य बनाम कुन्नथ चेल्लप्पन नायर और अन्य (जेटी 2005 (9) एससी 171), छदत सिंह बनाम बहादुर राम और अन्य (जेटी 2004 (6) एससी 296) और कन्हैयालाल बनाम अनुपकुमार (जेटी 2002 (10) एससी) 98).

6. इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय व्यावहारिक रूप से गैर-तर्कसंगत है। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया। इसलिए, चूंकि निर्णय व्यावहारिक रूप से गैर-तर्कसंगत है, इसलिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि उच्च न्यायालय को ऐसा क्यों लगा की विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को उलटना चाहिए। अतःहम धारा 100 सीपीसी के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में भेजते हैं।

7. अपील स्वीकार की जाती है। कोई हर्जा खर्चा नहीं.

एस.के.एस.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अविनाश चांघल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।